G7 एवियन में भारत के प्रस्ताव: “IMPACT” और AI पर सुझाव

अंतरराष्ट्रीय संबंध | समाचार संदर्भ: G7 शिखर सम्मेलन (एवियन, फ़्रांस) में प्रधानमंत्री के तीन संबोधन, 16-17 जून 2026 | प्रकाशित: 18 अक्टूबर 2026

पृष्ठभूमि और संदर्भ

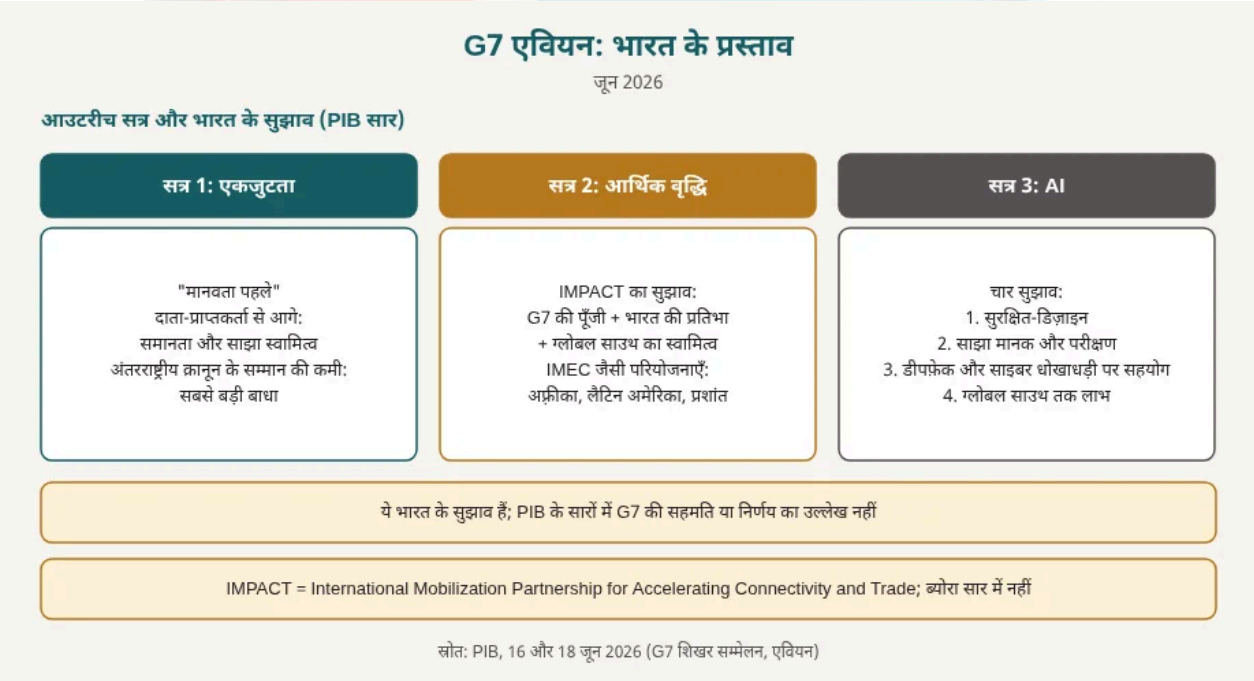
G7 सात औद्योगिक देशों का समूह है और भारत उसका सदस्य नहीं है; भारत को मेज़बान देश आउटरीच सत्रों में आमंत्रित करता है। आमंत्रित देश के नेता के संबोधन में अक्सर नीतिगत प्रस्ताव और अपेक्षाएँ होती हैं, पर वे समूह के निर्णय नहीं होते। इसलिए इन संबोधनों को पढ़ते समय यह देखना ज़रूरी है कि कौन-सी बात भारत का प्रस्ताव है और कौन-सी G7 की सहमति।

खबरों में क्यों

प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्थान-वक्तव्य (PIB, 13 जून 2026) के अनुसार वे 13 से 18 जून 2026 तक फ़्रांस और स्लोवाक गणराज्य की यात्रा पर थे और G7 शिखर सम्मेलन में 16 और 17 जून को शामिल हुए। PIB ने आउटरीच सत्रों में उनके तीन संबोधनों के सार जारी किए: “नई साझेदारियाँ और अंतरराष्ट्रीय एकजुटता का पुनर्निर्माण”, “संतुलित, साझा और टिकाऊ आर्थिक वृद्धि” और “AI का सुरक्षित, तेज़ और कुशल प्रसार”।

मुख्य अवधारणा: प्रस्ताव बनाम निर्णय

PIB के सार में प्रधानमंत्री ने “सुझाव दिया”, “आह्वान किया” और “प्रस्ताव रखा” जैसे रूप में बात रखी। जैसे IMPACT (International Mobilization Partnership for Accelerating Connectivity and Trade) का “सुझाव”; AI पर “चार सुझाव”। PIB के इन सारों में G7 की सहमति, घोषणा या किसी निर्णय का उल्लेख नहीं है। इसलिए इन्हें “भारत ने प्रस्ताव रखा” पढ़ें, “G7 ने अपनाया” नहीं।



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

मुख्य तथ्य और आंकड़े

अवसर	**G7 शिखर सम्मेलन, एवियन, फ़्रांस, 16-17 जून 2026। प्रस्थान-वक्तव्य में प्रधानमंत्री के अनुसार यह भारत को आमंत्रित किया गया लगातार आठवाँ G7 शिखर सम्मेलन है (प्रधानमंत्री का कथन)।**
सत्र 1: एकजुटता	प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार और प्रौद्योगिकी का "संकीर्ण हितों के लिए दुरुपयोग" हो रहा है, जिससे भरोसे की कमी है। "मानवता पहले" का सिद्धांत बताया और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, CDRI, वैश्विक जैव-ईंधन गठबंधन, मिशन LiFE और "एक पेड़ माँ के नाम" का उल्लेख किया। साझेदारी को दाता-प्राप्तकर्ता ढाँचे से आगे समानता और साझा स्वामित्व की ओर ले जाने और अंतरराष्ट्रीय क़ानून के सम्मान की कमी को सबसे बड़ी बाधा बताया।
सत्र 2: आर्थिक वृद्धि	वृद्धि केवल GDP या व्यापार के आँकड़ों से नहीं, लोगों के समावेशन और कल्याण से आँकी जाए। IMEC का उल्लेख। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से विकासशील देशों को आर्थिक लचीलापन देने वाले तंत्र बनाने का आह्वान। अफ़्रीका, लैटिन अमेरिका और प्रशांत द्वीप देशों को जोड़ने वाली IMEC जैसी कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर विचार का सुझाव। IMPACT: G7 की पूँजी, भारत की प्रतिभा और ग्लोबल साउथ के स्वामित्व को जोड़ने का सुझाव।
सत्र 3: AI	AI के प्रति भारत का "मानव-केंद्रित (MANAV)" दृष्टिकोण। चार सुझाव: AI प्रणालियाँ "सुरक्षित-डिज़ाइन" हों; साझा मानक, परीक्षण ढाँचे और नियामक दिशानिर्देश हों; डीपफ़ेक, दुष्प्रचार और साइबर धोखाधड़ी से निपटने में प्रभावी वैश्विक सहयोग हो; AI के लाभ ग्लोबल साउथ तक पहुँचें। साथ ही लोकतांत्रिक देशों के लिए ऐसे AI मॉडलों तक पहुँच की बात, जो महत्वपूर्ण सूचना-अवसंरचना को सुरक्षित रखें।
व्यापार का उल्लेख	प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत G7 के सदस्यों और कई अन्य देशों के साथ व्यापार समझौतों की दिशा में काम कर रहा है। सार में किसी विशेष समझौते का नाम नहीं है।

संबोधनों को कैसे पढ़ें

आउटरीच सत्र की प्रकृति: भारत G7 का सदस्य नहीं, आमंत्रित है। आउटरीच सत्रों के विषय मेज़बान तय करता है। PIB के सार मेज़बान की ओर से जारी कोई संयुक्त पाठ नहीं हैं; वे भारतीय पक्ष का सार हैं।

IMPACT का स्वरूप: सार के अनुसार IMPACT एक "सुझाव" है, जिसकी रूपरेखा, वित्त-पोषण या सदस्यता का ब्योरा सार में नहीं है। यह भी स्पष्ट नहीं कि G7 के किसी देश ने इसे अपनाया। इसलिए यह अभी विचार के स्तर पर है।

उदाहरणों की प्रकृति: प्रथम-प्रतिक्रियाकर्ता के उदाहरण (श्रीलंका, अफ़ग़ानिस्तान, मोज़ाम्बिक, जमैका) प्रधानमंत्री के संबोधन के अनुसार हैं। हमने इन घटनाओं के विवरण अलग से नहीं जाँचे।

यह विषय क्यों मायने रखता है

ग्लोबल साउथ की आवाज़: प्रस्थान-वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 में भारत "ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को भी स्वर देगा"। यह भारत के पक्ष का दावा है; PIB के पाठ में ग्लोबल साउथ के देशों की प्रतिक्रिया नहीं है।

कनेक्टिविटी और वित्त: IMPACT का प्रस्ताव IMEC के अनुभव पर बना बताया गया है। हमारे पाठ में यह प्रस्ताव कनेक्टिविटी के लिए पूँजी जुटाने की बाधा की ओर संकेत करता है; सार में निधि का कोई आँकड़ा नहीं है।

बहस के बिंदु और सावधानियाँ

परिणाम बनाम भाषण: हमने PIB के चार पाठ पढ़े। G7 का नेताओं का वक्तव्य या अध्यक्ष का सारांश हमने नहीं पढ़ा, इसलिए यह नहीं कह सकते कि IMPACT या AI पर सुझावों का उसमें क्या स्थान है। इसके बाद IMPACT पर किसी आधिकारिक

अनुवर्ती कार्रवाई की जानकारी हमने नहीं पढ़ी।

सत्र की तारीख़: PIB का पहला सार 16 जून को और अन्य दो 18 जून को जारी हुए। हम केवल शिखर सम्मेलन की तारीख़ें (16-17 जून) बता रहे हैं; हर सत्र की ठीक तारीख़ हमने PIB के पाठ से तय नहीं की।

स्रोत और सीमाएँ: पढ़े गए स्रोत: प्रस्थान-वक्तव्य (https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2272378&lang=1&reg=3), सत्र 1 (https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2273799&lang=1&reg=3), सत्र 2 (https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2274370&lang=1&reg=3) और सत्र 3 (https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2274371&lang=1&reg=3), सभी पूरे। द्विपक्षीय बैठकें हमने इस लेख में शामिल नहीं कीं।

पूर्व लेख से अंतर: pcsmantra.com पर इस G7 शिखर सम्मेलन पर लेख हमें नहीं मिला (खोज: “G7”, “जी7”, “Evian”, “IMPACT G7”)।

आगे की राह

इस लेख को 16-18 जून 2026 के PIB सारों की स्थिति के रूप में पढ़ें। G7 के आधिकारिक पाठ और IMPACT पर आगे की कार्रवाई आने पर निष्कर्ष बदल सकते हैं।

अवधारणा में अंतर

चार बातें अलग रखें: (1) भारत के प्रस्ताव और सुझाव; (2) G7 का कोई सहमत निर्णय (हमने नहीं पढ़ा); (3) प्रधानमंत्री के दावे और उदाहरण; और (4) हमारी व्याख्याएँ।

मेंस दृष्टि

GS-II: भारत और वैश्विक समूह; भारत के हितों पर विकसित देशों की नीतियों का प्रभाव; GS-III: AI और प्रौद्योगिकी। उत्तर में “प्रस्ताव” और “निर्णय” का फ़र्क़ ज़रूर लिखें।

UPSC CSE Mains शैली: मौलिक अभ्यास प्रश्न

G7 एवियन शिखर सम्मेलन (जून 2026) में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रखे गए प्रस्तावों का मूल्यांकन कीजिए और बताइए कि उन्हें ठोस रूप देने में क्या बाधाएँ हैं।

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) | 10 अंक

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: G7 आउटरीच में भारत की भूमिका।

मुख्य भाग में: तीन सत्र; IMPACT और AI के चार सुझाव; ग्लोबल साउथ का दृष्टिकोण; सीमाएँ: प्रस्ताव बनाम निर्णय, ब्योरे का अभाव।

निष्कर्ष में: IMPACT और AI संबंधी सुझावों को भारत के प्रस्ताव के रूप में ही प्रस्तुत करें; ग्लोबल साउथ की भागीदारी के उद्देश्य को ठोस नियम, वित्त और सहमति की उपलब्ध जानकारी के आधार पर परखें, G7 का निर्णय न मानें।

स्रोत

- PIB, प्रधानमंत्री का प्रस्थान-वक्तव्य, फ़्रांस और स्लोवाकिया यात्रा (13 जून 2026)
- PIB, G7 सत्र: नई साझेदारियाँ और अंतरराष्ट्रीय एकजुटता (16 जून 2026)
- PIB, G7 सत्र: संतुलित, साझा और टिकाऊ आर्थिक वृद्धि (18 जून 2026)
- PIB, G7 सत्र: AI का सुरक्षित, तेज़ और कुशल प्रसार (18 जून 2026)

G7 के आधिकारिक वक्तव्य, द्विपक्षीय बैठकें और IMPACT पर अनुवर्ती कार्रवाई नहीं पढ़ी गईं।

याद रखें: PIB के सारों के अनुसार प्रधानमंत्री ने G7 एवियन (16-17 जून 2026) में IMPACT कनेक्टिविटी साझेदारी और AI पर चार सुझाव रखे। ये भारत के प्रस्ताव हैं; G7 की सहमति या अनुवर्ती कार्रवाई हमने नहीं पढ़ी।